समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ललित मोहन जोशी*

शिक्षा न केवल व्यक्ति अपितु संपूर्ण राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयास होता है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के सभी नागरिकों को इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का हित हो। परंतु देश के प्रत्येक व्यक्ति की पृष्ठभूमि में विविधता है अर्थात् कई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई आदि कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसे वंचित तथा हाशिए के लोगों की शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए समाधान के रूप में समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय अस्तित्व में आया। इस प्रकार, इस संप्रत्यय पर भारत सहित वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि भारत में संविधान में आवश्यक संशोधन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समावेशी शिक्षा हेतु निर्धारित प्रावधान, 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009', 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' एवं सतत विकास लक्ष्य आदि जैसे प्रयासों के द्वारा सार्थक कार्य किए गए हैं। उनमें 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' उपर्युक्त समस्त प्रयासों को स्वयं में समाहित करते हुए, समावेशन की प्रक्रिया को शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में स्थापित कर एक नवीन आयाम प्रदान करती है। इन्हीं सरोकारों पर आधारित यह लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में निहित समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

शिक्षा मानव जाति के विकास की आधारशिला है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अकल्पनीय प्रगति की है, उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह शिक्षा प्रक्रिया ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य एवं अपरिहार्य आवश्यकता है। यही कारण

है कि वर्तमान में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में भी 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके माध्यम से छह से चौदह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। परंतु इसके पश्चात भी अनेक ऐसी बाधयताएँ हैं जिनके कारण प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सुलभ नहीं हो

पाता है। शारीरिक अक्षमता, सामाजिक-आर्थिक अपवंचन, भाषा एवं संस्कृति इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जो शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अपनाकर किया जा सकता है, जो इन समस्याओं से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ

समावेशी शिक्षा के समानांतर दो अन्य शब्द युग्मों 'विशिष्ट शिक्षा' एवं 'एकीकृत शिक्षा' का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। शिक्षाविदों के मध्य इन शब्दों के प्रयोग को लेकर कुछ मतभेद हैं। विद्वानों का एक वर्ग जहाँ इन तीनों शब्द युग्मों को एक-दूसरे का पर्याय मानता है, तो वहीं दूसरे वर्ग का मत है कि इन तीनों में अंतर है और इन्हें एक-दूसरे का पर्याय नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः सत्य यह है कि इन तीनों अवधारणाओं में समानता के साथ-साथ महत्वपूर्ण अंतर भी है। यह अंतर मुख्यतः कालक्रम एवं अवधारणा की व्यापकता के आधार पर है। शिक्षा के इन तीनों ही प्रकारों में मुख्यतः उन विशिष्टताओं को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है जिनके कारण इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त बच्चों की शिक्षा बाधित न हो सके। कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम 'विशिष्ट शिक्षा' का संप्रत्यय अस्तित्व में आया। जिसके द्वारा केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा देने का प्रयास किया गया। परंतु कुछ समय पश्चात यह अनुभव

किया जाने लगा कि इस प्रकार का पृथक्करण इन विशेष प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से पृथक् करने लगता है, जिसके कारण उनका मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भली-भाँति नहीं हो पाता।

इस अलगाव को दूर करने के लिए 'एकीकृत शिक्षा' का संप्रत्यय अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के एकीकरण पर बल दिया जाने लगा। परंतु इस प्रकार की शिक्षा में भी केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने की अवधारणा पर बल दिया गया। इस अवधारणा से विशिष्ट शिक्षा की कमियों का कुछ सीमा तक तो समाधान हुआ, परंतु यह व्यवस्था उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने में विफल रही जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भाषा के आधार पर वंचित समूहों से थे। एकीकृत शिक्षा के इस प्रमुख दोष के निवारण हेतु एक नवीन प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, जिसे 'समावेशी शिक्षा' कहा जाता है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा का वह रूप है जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं इसी प्रकार की अन्य विशेषताओं के आधार पर वंचित समूह के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य इन बच्चों के व्यक्तित्व के विविध पक्षों का विकास कर उन्हें अपनी जीवनवृत्ति के योग्य, कुशल, दक्ष एवं मानवीय बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

वैश्विक संदर्भ में समावेशी शिक्षा संबंधी प्रयासों का संक्षिप्त इतिहास

समावेशी शिक्षा का प्रारंभ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से माना जा सकता है। वैश्विक संदर्भ में इसका श्रेय दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने संबंधी प्रयासों को जाता है। शर्मा (2010) के अनुसार, फ्रांस के इटार्ड (1775-1835), ऐडवर्ड सेग्विन (1812-1880), अल्फ्रेड बिने (1857-1911), इटली की मारिया मॉण्टेसरी (1870-1952) द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से प्रयास करने का श्रेय बेल्जियम के अध्यापक और मनोवैज्ञानिक ओविड डेक्रॉली (1871-1932) को जाता है। उन्होंने मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण एवं विद्यालयों की स्थापना की थी। तत्पश्चात विज्ञान तथा तकनीकी के विकास के परिणामस्वरूप निर्मित विविध प्रकार के उपकरणों एवं इस क्षेत्र विशेष के प्रति संवेदनशील विद्वानों के द्वारा निर्मित उपकरणों एवं शिक्षण विधियों ने विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

वैश्विक संदर्भ में 'समावेशी शिक्षा' शब्द का प्रचलन 1994 से बढ़ा। इस वर्ष 7-10 जून 1994 तक स्पेन के सलामांका में यूनेस्को द्वारा 'वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन— एक्सेस एण्ड क्वालिटी' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 92 देशों एवं 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन की रिपोर्ट 1995 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आठवें पृष्ठ के बिंदु संख्या दो में यह कहा गया, "नियमित विद्यालय, समावेशी उन्मुखीकरण के साथ भेदभावपूर्ण

दृष्टिकोण का मुकाबला करने, स्वागत करने वाले समुदायों का निर्माण करने, एक समावेशी समाज निर्मित करने और सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के प्रभावी साधन हैं। इसके अतिरिक्त वे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करते हैं, दक्षता में सुधार करते हैं और अंततः संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की लागत प्रभावशीलता में सुधार करते हैं।"

इसके पश्चात वर्ष 2000 में 26-28 अप्रैल तक डकार (सेनेगल) में 'वर्ल्ड एजुकेशन फोरम' का आयोजन किया गया था। इस वैश्विक मंच से 'सभी के लिए शिक्षा' आंदोलन को नवीन गति प्रदान करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही इस फोरम में निर्धन, ग्रामीण, दूर-दराज के समुदायों के साथ जातीय अल्पसंख्यकों और जनजातीय समूहों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया। इन प्रयासों के पश्चात समावेशी शिक्षा की अवधारणा का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ और इस ओर विशेष प्रयास किए जाने प्रारंभ हुए।

भारत में समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास संजीव (2008) के अनुसार भारत में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ सार्जेंट रिपोर्ट (1944) से माना जाता है। जिसमें यह उल्लिखित है, "मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होना चाहिए तथा इसका प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।" इसके साथ ही सार्जेंट रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है, "जहाँ तक सम्भव हो अक्षमता से युक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से पृथक नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें विशेष विद्यालयों में तभी भेजा जाना चाहिए जब उनकी दोष की प्रकृति एवं सीमा

के कारण यह आवश्यक हो जाए।” इसके साथ ही रिपोर्ट में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की व्यवस्था करने एवं इस प्रकार के बच्चों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया है।

स्वतंत्रता के उपरांत कोठारी आयोग (1964–66) द्वारा अनुशांसा की गई कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अविच्छिन्न अंग होनी चाहिए। कोठारी आयोग की इसी अनुशांसा के आधार पर भारत में ‘दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा’ प्रारंभ हुई। इसके पश्चात 1986 की शिक्षा नीति एवं 1992 की कार्ययोजना में भी निःशक्त बच्चों की शिक्षा हेतु उन्हें सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान करने, निःशक्तता का स्तर गंभीर होने की दशा में विशेष विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने एवं इनकी आवश्यकतानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करने संबंधी सुझाव दिए गए। तत्पश्चात 1995 में निःशुल्क व्यक्ति अधिनियम में भी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, एकीकृत शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत 1997 में ‘जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम’ एवं 2000 में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के द्वारा भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह सुझाव दिया गया है कि समावेशन की नीति को समस्त विद्यालयों और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाए। अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में समावेशी शिक्षा को महत्व प्रदान करते हुए अध्यापकों को इसके दर्शन के प्रति जागरूक

करने का सुझाव दिया गया है। *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016* के अध्याय तीन में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस अध्याय की प्रथम पंक्ति में ही यह उल्लिखित है, “समुचित सरकार और स्थानीय पदाधिकारी यह प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिव्यांग बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें एवं अन्य आवश्यक उपाय भी करें।” भारत सरकार द्वारा 2018–19 में विद्यालयी शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चार भागों में विभाजित है, जो इस प्रकार है—

भाग 1— स्कूल शिक्षा

भाग 2— उच्चतर शिक्षा

भाग 3— अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

भाग 4— क्रियान्वयन की रणनीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसकी पुष्टि इस नीति के परिचय में उल्लिखित इस कथन से होती है, “भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है।” इस नीति के

आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है, “इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक व्यक्तियों को तैयार करना है जो कि संविधान द्वारा परिकल्पित, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।” इसके अतिरिक्त आधारभूत सिद्धांतों में यह भी कहा गया है, “एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी विद्यार्थियों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढाँचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं।” इसके साथ ही इस नीति के प्रथम मूलभूत सिद्धांत में यह वर्णित है, “प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करने के प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए।”

उक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभ से ही समावेशन की प्रक्रिया को संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान प्रदान करती है। इस नीति में समावेशी शिक्षा का वर्णन दो स्थानों प्रथम, भाग 1 (स्कूली शिक्षा) के छठे अध्याय में ‘समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम’ शीर्षक से एवं द्वितीय, भाग 2 (उच्चतर शिक्षा) अध्याय 14 ‘उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश’ शीर्षक से किया गया है। अध्याय छह के विविध बिंदुओं के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही समावेशी शिक्षा के महत्व

एवं लक्ष्य का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है, “समतामूलक और समावेशी शिक्षा न केवल स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, अपितु समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है। यह नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है, जिससे भारत के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियाँ बाधक न बन पाएँ।”

इस अध्याय (एन.ई.पी. 2020, अनुच्छेद 6.2) में भी यह चिंता व्यक्त की गई है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह वर्तमान में भी पिछड़ी हुई स्थिति में है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) को पृथक-पृथक आधारों पर इस प्रकार विभाजित किया गया है—

- जेंडर— विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर
- सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक
- भौगोलिक पहचान— गाँव, कस्बे व आकांक्षी जिले संबंधित अक्षमता सहित के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता सीखने से अक्षमता युक्त बच्चे
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति— प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे, जिनमें अनाथ बच्चे, शहरों में भीख माँगने वाले बच्चे व शहरी गरीब बच्चे सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर की तुलना में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वंचित समूहों के नामांकन के प्रतिशत में होने वाली न्यूनता पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है जो तालिका 1 में दिए गए विवरण से स्पष्ट होती है—

तालिका 1— वर्गवार प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत

वर्ग	प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत	उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत	नामांकन में कमी प्रतिशत में
अनुसूचित जाति	19.6	17.3	2.3
अनुसूचित जनजाति	10.6	6.8	3.8
दिव्यांग	1.1	0.25	0.85

स्रोत – यू-डायस 2016–17 प्रकाशित रा.शि.नी. 2020, 6.2.1 पृ.सं. 38

तालिका 1 के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वंचित समूहों (अनुसूचित जाति) में जहाँ प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत 19.6 प्रतिशत है, वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक आते-आते इसमें और गिरावट (17.3 प्रतिशत) प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार की स्थिति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन के संदर्भ में भी प्रदर्शित होती है। तालिका 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन के संदर्भ में यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तालिका 1 में वंचित समूहों के नामांकन में कमी के कारणों पर भी विचार किया गया है। इसमें यह माना गया है कि गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त न कर पाना, निम्न आर्थिक स्तर, सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ, भाषा, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ अल्प शैक्षिक नामांकन के प्रमुख कारण हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में न केवल इन वंचित वर्गों के अल्प शैक्षिक नामांकन के कारणों का उल्लेख किया गया है, अपितु इनके समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। जिसमें लक्षित छात्रवृत्ति, सशर्त नकद हस्तांतरण, आवागमन हेतु

साइकिल प्रदान करना, शहर के निर्धनता बाहुल्य क्षेत्रों में काउंसलर अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध कराना, वंचित आबादी के बाहुल्य वाले क्षेत्रों को 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' घोषित करना, इन वर्गों के उत्थान हेतु बनाई जाने वाली योजनाओं में बालिकाओं को केंद्रीय स्थान प्रदान करना इत्यादि मुख्य हैं। समावेशी शिक्षा के संबंध में इस नीति में एक नवीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है, "भारत सरकार सभी बालिकाओं के साथ ही ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर— समावेशी निधि' का गठन करेगी।"

समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह कथन वास्तव में समावेशन की अवधारणा को एक नवीन आयाम प्रदान करता है, क्योंकि इस नीति में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा पर गंभीरतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है। समावेशी शिक्षा को और अधिक बल प्रदान करने एवं व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए इस नीति में उन स्थानों पर जवाहर नवोदय विद्यालयों की भाँति निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण करने का सुझाव दिया गया है, जहाँ विद्यालय

जाने के लिए विद्यार्थियों को बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही, इनमें बालिकाओं की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को सुदृढ़ करने, *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016* के अनुरूप इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने, उनकी शिक्षा हेतु विशेष अध्यापकों की नियुक्ति करने, उनके लिए बाधा मुक्त भवनों का निर्माण करने, उपयुक्त शिक्षण सामग्री निर्मित करने, उन्हें बुनियादी विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा उच्चतर गुणवत्ता वाले मॉड्यूलस का निर्माण करने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

दिव्यांगता, समावेशी शिक्षा का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है। इस नीति में इस पक्ष पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए यह सुझाव दिया गया है कि मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित अथवा विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। साथ ही, यह भी कहा गया है कि विद्यालय जाने में असमर्थ, गंभीर और गहन दिव्यांग बच्चों को 'गृह आधारित शिक्षा' का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इन बच्चों को सामान्य प्रणाली में शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य बच्चों के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच हेतु 'समता व अवसर की समानता' के सिद्धांत पर ऑडिट कराया जाएगा। सीखने की दृष्टि से विशिष्ट अक्षमतायुक्त बच्चों को सीखने में निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार के बच्चों की जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र सहायता प्रदान करने का सुझाव भी इस नीति में दिया गया है। शिक्षा नीति में इस प्रकार के

बच्चों को अपनी गति के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने एवं पाठ्यक्रम को प्रत्येक बच्चे की क्षमतानुसार सक्षम एवं लचीला बनाने का सुझाव भी दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'परख' नामक नवीन राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इस संस्था का कार्य अन्य प्रमाण संस्थाओं के साथ मिलकर मूल्यांकन के उपयुक्त तरीकों से संबंधित सुझाव देना होगा, जिससे कि सीखने की अक्षमता वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की असमानताओं को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति में इन समूहों के प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रावास, सेतु पाठ्यक्रम, शुल्क मुक्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करने का सुझाव दिया गया है, जिससे उच्चतर शिक्षा में उन्हें सरलता से प्रवेश मिल सके।

जनजाति बहुल प्रदेशों के निवासियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस नीति में कहा गया है कि इन प्रदेशों में रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को अपने माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. विंग की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी अद्वितीय प्राकृतिक क्षमता का प्रयोग रक्षा सेवा में किया जा सकेगा और उन्हें भी उचित जीवनवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को सुदृढ़ बनाने के लिए इस नीति में यह कहा गया है कि विद्यालय की संस्कृति में अपेक्षित बदलाव कर सभी व्यक्तियों की निजता के प्रति संवेदनशील होने, उन्हें सम्मान व

प्रतिष्ठा प्रदान करने से एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकेगा जो अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होगा।

इन प्रयासों के द्वारा समावेशन और समता 'अध्यापक शिक्षा' का प्रमुख पक्ष बन जाएँगे। यदि सामाजिक-आर्थिक इत्यादि रूप से वंचित समूहों में से उच्चतर गुणवत्तायुक्त व्यक्तियों का शिक्षण एवं नेतृत्वकर्ता जैसे क्षेत्रों हेतु चयन किया जा सके तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो सकेगा।

अंत में, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह कहा गया है कि विद्यार्थी पूर्वोक्त प्रयासों से निर्मित इस नई एवं समावेशी विद्यालयी संस्कृति को आत्मसात कर सकें। इस हेतु अध्यापकों, अन्य विद्यालय कर्मियों एवं पाठ्यक्रम के द्वारा उन्हें संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाएँगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम से प्रत्येक प्रकार के पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को दूर कर सभी समुदायों से संबंधित, मानवीय मूल्यों से युक्त और प्रासंगिक पाठ्यवस्तु को प्रमुखता से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्याय 14 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में समता एवं समावेशन संबंधी विचार व्यक्त किए गए हैं तथा इस अध्याय को अध्याय छह के पूरक भाग के रूप में समझे जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अध्याय 14 के प्रथम बिंदु में इस संदर्भ में कहा गया है, "उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार सम्भावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों के साथ ही समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता

है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह पर विशेष ज़ोर देते हुए सभी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्वोक्त वर्णित वंचित समूहों के उच्चतर शिक्षा में प्रवेश प्राप्त न कर पाने के कारण भी बताए गए हैं। जिनमें उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, निम्न आर्थिक स्तर, प्रवेश प्रक्रिया, भौगोलिक बाधाएँ, भाषाई अवरोध, उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित रोज़गार क्षमता एवं विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान पर विचार करते हुए यह नीति इस हेतु जहाँ एक ओर सरकार द्वारा किए जाने वाले समाधान प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी समुचित उपाय करने संबंधी सुझाव प्रदान करती है। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश हेतु प्रस्तावित कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं—

1. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के लिए सरकारी निधि का निर्धारण;
2. उच्चतर सकल नामांकन अनुपात तथा इन वर्गों हेतु स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण;
3. प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना;
4. सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन वंचित वर्गों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;

5. वंचित वर्गों के मध्य उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से संबंधित जागरूकता का प्रसार करना।

इस शिक्षा नीति में वर्णित उच्चतर शिक्षण संस्थानों से अपेक्षित कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं—

1. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना;
2. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;
3. प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना;
4. पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना;
5. उच्चतर शिक्षा को अधिक रोजगारपरक बनाना;
6. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भवन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएँ दिव्यांगजनों के अनुकूल हों;
7. भेदभाव तथा उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए निर्मित नियमों को दृढ़ता से लागू करना।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को केंद्र में रखकर बनाई गई है तथा इस संबंध में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों, चुनौतियों एवं उनके समाधान पर व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान एवं समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण प्रयास समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। यद्यपि इस अभियान का प्रारंभ वर्ष 2018-19 में

हुआ। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अस्तित्व में आने के उपरांत समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। इस अभियान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। जिसमें सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) को भी सम्मिलित किया गया है। इस अभियान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा एवं अध्यापक को भी सम्मिलित किया गया है। इस अभियान के द्वारा विद्यालयों में आधारभूत संरचना, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का मूल उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता एवं समावेशन को सुनिश्चित करना है। इस अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं एवं बच्चों की विविध क्षमताओं पर बल दिया जाना है। इसके साथ ही, इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा उनकी अधिगम की उपलब्धियों में वृद्धि करना है। इस हेतु आगामी कुछ वर्षों में चरणबद्ध रूप में विद्यालयों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा-कक्ष एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सेनेटरी पैड इत्यादि की व्यवस्था करना निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों की दक्षता विकास को

ध्यान में रखते हुए कक्षा 9–12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यचर्या के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत रूप में प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत धनराशि प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अभियान में अध्यापकों की क्षमताओं के विकास एवं प्रशिक्षण कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्य में रा.शै.अ.प्र.प. अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इस नीति में समावेशी शिक्षा को संपूर्ण नीति के केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसकी पुष्टि नीति के पाँचवें पृष्ठ में उल्लिखित इस कथन से होती है जिसमें कहा गया है, “शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है।”

इसके साथ ही इस नीति के आधारभूत सिद्धांतों में भी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस नीति का उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो संविधान द्वारा परिकल्पित, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में भली-भाँति योगदान दे सकें।

प्रथमतः इस शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार करते हुए पृथक रूप से दो अध्यायों (अध्याय 6 एवं अध्याय

14) के अंतर्गत सुव्यवस्थित रूप में समावेशी शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त महत्वपूर्ण स्थलों पर भी शिक्षा नीति को समावेशी शिक्षा के अनुकूल बनाने का प्रयास भी किया गया है।

अध्याय 6 में विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रावधानों पर विचार किया गया है। इस अध्याय की संपूर्ण विषयवस्तु मुख्यतः चार भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में समावेशी शिक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे भाग में उन समस्त समूहों का वर्णन है जो कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य आधारों पर वंचित समूहों के अंतर्गत आते हैं, तीसरे भाग में इन समूहों के विद्यालयी शिक्षा में अल्प नामांकन के कारणों का उल्लेख किया गया है तथा चौथे भाग में व्यवस्थित रूप से उन सुझावों का समावेश किया गया है, जिनसे इन समूहों के नामांकन में वृद्धि करने के साथ उनकी क्षमतानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व उसका समुचित मूल्यांकन करने संबंधी सुझाव दिए गए हैं। अध्याय 14 में उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन संबंधी सुझाव पूर्वोक्त की भाँति दिए गए हैं। इस अध्याय में उच्च शिक्षा में समता और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा इस क्षेत्र में किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित सुझाव दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण नवीन सुझाव दिए गए हैं जो निम्नवत हैं—

- पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को इन वंचित वर्गों में सम्मिलित कर इस नीति ने समावेशी शिक्षा

को नया आयाम प्रदान किया है। यह निःसंदेह एक क्रान्तिकारी सुझाव है जो यदि व्यावहारिक रूप से लागू हो जाए तो इस समुदाय की दशा एवं दिशा में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है।

- गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को 'गृह आधारित शिक्षा' का विकल्प प्रदान करने एवं इन बच्चों को सामान्य प्रणाली में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के समतुल्य मानने संबंधी सुझाव भी इस क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- गृह आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता की जाँच हेतु समता व अवसरों की समानता के सिद्धांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन संबंधी सुझाव भी नीति-निर्माताओं की संवेदनशीलता एवं दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है।
- दिव्यांग एवं विशिष्ट अक्षमतायुक्त बच्चों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित, 'परख' जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना एवं इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण, इस क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाला प्रयास सिद्ध हो सकता है।
- समावेशन को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने का प्रयास निःसंदेह ही सर्वोत्कृष्ट है। इससे व्यावहारिक रूप में अध्यापकों की नयी पीढ़ी को इस कार्य के लिए संवेदनशील बनाया जा सकेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापक अपने पेशे में प्रवेश कर अन्य विद्यार्थियों, विद्यालय कर्मियों एवं समाज को इन वंचित समूहों की शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने का कार्य करेंगे।
- वंचित वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों में से अध्यापक और नेतृत्वकर्ताओं के चयन का सुझाव भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। यह इस वर्ग

के अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार प्राप्ति हेतु प्रेरित करेगा।

- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह सुझाव भी दिया गया है कि जनजातीय बहुल प्रदेशों में माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. विंग स्थापित की जाएगी। जिससे जनजातीय विद्यार्थियों की प्राकृतिक प्रतिभा एवं क्षमता का सदुपयोग रक्षा सेनाओं में किया जा सकेगा। यह सुझाव न केवल इन समुदायों के लिए ही हितकर होगा अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सहायक सिद्ध होगा।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में समावेशी शिक्षा पर संवेदनशीलता के साथ गहनतापूर्वक विचार कर व्यावहारिक सुझाव प्रदान किए गए हैं। शिक्षा नीति में यू-डाइस के आँकड़ों के माध्यम से इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है कि कुछ वर्ग विशेष के विद्यार्थियों के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों का नामांकन, इन्हीं वर्गों के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों से कम है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कि प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक पहुँचने में नामांकन में कमी प्रदर्शित हो रही है। जिसके लिए व्यवस्थित एवं निष्पक्ष सर्वेक्षण के माध्यम से नामांकन में होने वाली न्यूनता के कारणों को खोजकर उनके लिए उचित उपायों का निर्धारण कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किए जाने वाले कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'समावेशन' को शिक्षा दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है, जिसे नीति का अभिन्न पक्ष मानते हुए, समावेशी शिक्षा एक कार्ययोजना 'सार्थक' निर्मित कर क्रमिक एवं को नवीन आयाम प्रदान करते हुए इसे व्यापक व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

संदर्भ

- एम.एस.जे.ई. 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016. भारत का राजपत्र.
- कुमार, संजीव. 2008. विशिष्ट शिक्षा. जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली.
- पाठक, पी.डी. 2007. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ. अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा.
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार.
- यूनाइटेड नेशंस. 2000. वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इन डकार, सेनेगल, 26-28 अप्रैल टू बूस्ट ड्राइव फॉर एजुकेशन फॉर ऑल: यूनाइटेड नेशंस 2000.
- यूनेस्को. 1994. वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन— एक्सेस एंड क्वालिटी. यूनेस्को. 3 फरवरी 2022 को <https://unesdoc.unesco.org> से लिया गया है.
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. समावेशी शिक्षा-कानूनी एवं नीतिगत ढाँचा. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.
- शर्मा, आर.एस. 2010. विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.
- समग्र शिक्षा अभियान. 8 फरवरी 2022 को <https://pmmodiyojna.in/samagra-shiksha-abhiyan/> से लिया गया है.